·488

HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 18, 1987 (SRVN. 27, 1909 SA KA)

सं. स्रो. वि. एफ.डी./गुडगाव/126-87/27171--चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० केंफको, दौलताबाद रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री विश्व नाथ, पुत्र श्री राम लखन, मार्फत श्री महाबीर त्यागी, ग्रीरगेनाईजर, इण्टक, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों ने मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिप्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक ग्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामलें हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :--

क्या श्री विश्वनाथ की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं ग्रो वि. यमुना/30-87/27178.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा (2) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री राम सरूप, गांव ग्रहमदपुर, डा० सलाहपुर, बाया सढ़ौरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवास है ;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिये, ग्रव, ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं-3 (44)-83-श्रम. 3, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उन से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 🛰 विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्वन्धित मामला है :---

क्या श्री राम सरूप की सेवाग्रों का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो वि./एफ ०डी ०/गुड़गांव/114-87/27185.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० इण्डो निप्पन फुडज प्रा० लि०, 7, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पालम गुड़गांव रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्रीमती हंस मुखी, मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज ऐसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, तथा प्रवन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का त्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ऋधिनियम को धारा 7-क के श्रधीन गठित श्रौद्योगिक श्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे, विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला /मामले हैं श्रथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामना/मामले है न्यायनिर्गय पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:---

> क्या श्रीमती हंस मुखी की प्रवन्धकों द्वारा सेवा समाप्त की गई या उसने चुकती हिसाब लेकर स्वयं नौकरी छोड़ी है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत की हकदार है?

सं० ग्रो० वि० एफ.डी./50-87/27192.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं पूर्वा इंजीनियर्ज लि० 12/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री समसुल हक, मार्फत एटक श्राफिस, एन. ग्राई. टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामलें के सम्बन्ध में कोई ख्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, म्रंब, म्रौद्योगिक विवाद म्रधिनियम, 1947,को धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के प्रधीन गठित ग्रौद्योगिक ग्रधिकरण हरियाणा, फरीदावाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं ग्रथवा विवाद से सुसंगत पा सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री समसुल हक की सेवा समाप्त की गई हैया उसने स्वयंही अपनी इच्छा से च्कती हिनाव प्राप्त कर के नौकरी छोड़ी है? इस बिन्दुपर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहन का हकदार है?

सं ग्रो० वि० एफ.डी./148-87/27199.—चूंकि हरियाणा के राज्यवाल की राये हैं कि मैं० प्रवीन रिनफोर्सड क्लास्टिक प्रा० लिए, प्लाट तंर 135, डी. एल. एफ., मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री अलाऊदीन, पुत्र श्री जैनुल शाह मार्फत हिन्द मजदूर सभा. 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इम के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में लोडे ग्रीडोगिक विवाद है,

भ्रोर चुकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्याया निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसिलिए अब. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के घण्ड (घ) हारा अदान की गई शिव्यों का प्रयोग करते हुए हिरियाणा के राज्यपाल इस केंद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन अधिन आँद्योगिक अधिकरण हिन्याणा, परीदाधाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला को कि उक्त प्रवन्थकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादस्थन मामला है अश्वा विवाद से ससंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 माम मे देने हेतु निदिष्ट जरते हैं—

वया श्री अलाऊदीन की सेवाओं हा समापन सायोजित तथा ठीक है ? यदि वहीं, तो वह किस सहत का हकदार है ?

यं. और वि एफ.डी./गुड़मांप/116-87/27206.—चूंकि हरियाणा के राज्यपात की राये हैं कि मैं अमिकॉन रेलवे रोड़, गुड़मांव के श्रमिक श्रो मदन लाल, पुत्र श्री जांजी राम, मधान नं 2678 अर्जन नगर, गुढ़ड़गांव तथा प्रवस्थकों के मध्य इमें इसस के बाद लिखित भामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्याय- निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इमिलए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है ऋथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट ,3 मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री मदन लाल की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है?

सं ग्रों वि एप,डी./गृड़गांव/143-87/27213.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं वैस्ट्रन इंडिया इण्डस्ट्रीज लिं , 55, इण्डस्ट्रीयल इंस्टेट पालम, गृड़गांव रोड़, गृड़गांव के श्रमिक श्री मोहिन्द्र पाल मेहता मार्फत श्री पी. के थम्पी जनरल सैकेटरी बी-II ग्राई. डी. पी. एल. टाउनिणप, गृड़गांव तथा प्रवन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रौद्योगिक विवाद है, श्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, ग्रव, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई गक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ग्रिधिनियम की धारा 7क के ग्रिधीन गठित ग्रीद्योगिक ग्रिधिकरण, हरियाणा, के फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रीमकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं झथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मोहिन्द्र पाल मेहता की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

स० म्रो० वि० एफ.डी./गुड़गांव/137-87/27220.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये हैं कि मै० वेस्ट्रन इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम, गुड़गांव रोड़, गुड़गांव के श्रमिक श्री मतंबर सिंह माफंत श्री पी. के. यम्पी, जनरल सैकेटरी, बी-II ग्राई. डी. पी. एल. टाऊनिशप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रांदोगिक विवाद है;

भ्रौर चंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रब, ग्रीडोगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ग्रिधिनियम की धारा 7-क के ग्रिधीन गठित ग्रीडोगिक ग्रिधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रिक्किं के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं ग्रथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

> क्या श्री मतबर सिंह की सेवाग्रों का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ग्रो०वि०पानीपत/19-87/27226.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चंडीगढ़, (2) कार्यकारी ग्रिभियन्ता, सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, थर्मल पावर प्रोजैक्ट एच०एस०ई०बी० ग्रासन, पानीपत के श्रमिक श्री सत नारायण मार्फत भारतीय मजदूर संघ जी०टी० रोड़, पानीपत क्षिया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं:

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3 श्रम/ दिनांक 18-4-84 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है:—-

क्या श्री सत नारायण, पुत्र श्री दरिया सिंह की सेवाग्नों का समापन/छटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है;

सं. द्यो. वि. एपडी/66-87/27234.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सिकन्दस लि०, 61, न्यू इण्डस्ट्रीयल टाऊनिशप, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहन लाल मार्फत श्री के एल शर्मा, उप प्रधान हरियाणा इन्द्रक जी-15, ग्रील्ड प्रैस कालोनी, फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के, मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

भ्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए ग्रब, ग्रीबोगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ग्रिधिनियम की धारा 7-क के ग्रिधीन गठित ग्रीबोगिक ग्रिधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है ग्रथवा विवाद से संतुलन सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री मोहन लाल सैटर की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?